



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]
No. 35]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

सं. टीएमपी/15/2000-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार पृथक्कृत बैलास्ट टैंकों वाले टैकरों के कम किए गए सकल टनभार के अनुसार पत्तन देयताओं की वसूली के बारे में निर्णय करता है।

अनुसूची

मामला सं० टीएमपी/15/2000—पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी)

.... गैर—आवेदक

आदेश

(मार्च, 2000 के 15वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला पृथक्कृत बैलास्ट टैंकों वाले टैकरों के कम किए गए सकल टनभार के संदर्भ में पत्तन देयताओं की वसूली से संबंधित है और उक्त विषय पर नौवृहन महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 5 अगस्त, 99 के परिपत्र सं० ईएनजी/टन/विद्युत के कारण उत्पन्न हुआ है।

2.1 पता चला है कि इंटररेनशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन (आईएमओ) ने तेल टैंकरों में पृथक्कृत बैलास्ट टैंकों के टनभार मापों से संबंधित एक प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें परामर्श दिया गया है कि ऐसे पोत के अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र में टिप्पणी के नीचे पृथक्कृत बैलास्ट टैंकों के टनभार के संबंध में प्रविष्टि की जानी थी। इस प्रस्ताव का आशय शुल्क निर्धारण के समय पृथक्कृत बैलास्ट क्षमता वाले तेल टैंकरों के कम किए गए सकल टनभार का प्रयोग करने के लिए पत्तन/बंदरगाह अधिकारियों से अनुरोध करना था। नौवहन महानिदेशक ने संदर्भगत अपने परिपत्र में आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्तन न्यासों के ध्यानार्थ इस स्थिति का उल्लेख किया है और उन्हें आगे परामर्श दिया है कि वे अपने टनभार प्रमाणपत्र के “टिप्पणी” कॉलम में ऐसे पोतों के कम किए गए सकल टनभार का उल्लेख करें। पृथक्कृत बैलास्ट वाले तेल टैंकरों के संबंध में यह विशेष रूप से सुझाव दिया गया है कि पत्तन देयताएं उक्त कम किए गए टनभार के अनुसार वसूल की जाएं।

2.2 इस परिपत्र पर कार्रवाई करते हुए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) ने नौवहन महानिदेशक के परिपत्र में दिए गए परामर्श के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने “दरों के मान” में “पोत—संबद्ध प्रभार” शीर्षक के नीचे एक नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

2.3 यद्यपि यह मामला पीपीटी के उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है, चूंकि इस मामले में कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान रूप से अपनाए गए सिद्धान्त को शामिल करने के लिए सभी पत्तन न्यासों को नौवहन महानिदेशक द्वारा भेजे गए एक परिपत्र से आरंभ हुई है, इसलिए इस प्राधिकरण ने इसे सभी महापत्तन न्यासों पर लागू मामले के रूप में मानने का निर्णय किया है।

3. इस मामले की जांच—पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में और समग्र ध्यान देते हुए निम्नलिखित निर्णय किए गए हैं:—

- (i) “चूंकि, पीपीटी का प्रस्ताव आईएमओ द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के संदर्भ में नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र पर आधारित है, इसलिए इस मुददे को बिना आगे किसी जांच—पड़ताल के ज्यों का त्यों स्वीकार किया जा सकता है।
- (ii) चूंकि, इस मामले में कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान रूप से अपनाए गए सिद्धान्त को शामिल करने के लिए सभी पत्तन न्यासों को साझा तौर पर नौवहन महानिदेशक द्वारा भेजे गए एक परिपत्र से आरंभ हुई है, इसलिए इस आदेश को सभी महापत्तन न्यासों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है।
- (iii) इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप में कियान्वित किया जा सकता है, यदि सभी महापत्तन न्यास “पत्तन देयताएं” शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित खंड को उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए अपने दरों के मान में संशोधन कर लेते हैं:—
“पृथक्कृत बैलास्ट वाले तेल टैंकरों के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय एवं टनभार प्रमाणपत्र के “टिप्पणी” कॉलम में उल्लिखित कम किए गए सकल टनभार को इसका सकल टनभार माना जाएगा।”

4. सभी महापत्तन न्यासों को एतद्वारा अपने दरों के मान में उपयुक्त परिवर्तनों को शामिल करने का निदेश दिया जाता है।

5. यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रभावी हो जाएगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/2000-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

No. TAMP/15/2000-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby decides about charging Port Dues with reference to the reduced gross tonnage of tankers with segregated ballast tanks, as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No.TAMP/15/2000-PPT

The Paradip Port Trust

Non-Applicant

ORDER

(Passed on this 15th day of March 2000)

This case relates to charging of Port Dues with reference to the reduced gross tonnage of tankers with segregated ballast tanks, and arises from Circular No.ENG/TON/Misc. dated 5 August 99 issued on the subject by the Director General of Shipping.

2.1. The International Maritime Organisation (IMO) had reportedly adopted a Resolution concerning tonnage measurements of segregated ballast tanks in oil tankers with the advice that, in the International Tonnage Certificate of such a vessel, under "Remarks" an entry was to be made for the tonnage of segregated ballast tanks. This Resolution was meant to move the Port/Harbour Authorities to use the reduced gross tonnage of oil tankers with segregated ballast capacity while assessing fees. In his circular in reference, the Director General of Shipping has drawn this position to the attention of the Port Trusts for necessary action; and, has further advised them to reflect the reduced gross tonnage of all such vessels in the 'remarks' column of their tonnage certificates. It has also been specifically suggested that, for oil tankers with segregated ballast, Port Dues may be charged with reference to the said reduced gross tonnage.

2.2. Acting on this circular, the Paradip Port Trust (PPT) has proposed introduction of a new clause under Head “Vessel-Related Charges” in its Scale of Rates to enable action as advised in the circular of the Director General of Shipping.

2.3. Although this case has arisen with reference to the said proposal of the PPT, since action in this matter has originated from a circular of the Director General of Shipping commonly to all the Port Trusts for incorporation of a principle that has been uniformly adopted internationally, this Authority has decided to treat this as a case applicable to all the major Port Trusts.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, and based on a collective application of mind, the following decisions are taken:

- (i). Since the PPT proposal is based on a circular issued by the Director General of Shipping with reference to a Resolution adopted by the IMO, the issue in reference can be accepted at face value without any further scrutiny.
- (ii). Since the action in this matter has originated from a circular issued by the Director General of Shipping commonly to all the major Port Trusts for incorporation of a principle that has been uniformly adopted internationally, this order can be made equally applicable to all the major Port Trusts.
- (iii). This proposition can be effectively implemented if all the major Port Trusts amend their Scale of Rates to incorporate the following clause appropriately under the Heading ‘Port Dues’:

“For oil tankers with segregated ballast, the reduced gross tonnage that is indicated in the ‘Remarks’ column of its International Tonnage Certificate will be taken to be its gross tonnage.”

4. All the major Port Trusts are hereby directed to introduce appropriate changes accordingly in their Scale of Rates.

5. This Order shall come into effect on expiry of thirty days from the date of publication of this Order in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman

[No. Advt./III/IV/143/2000-Exty.]